

सान्ध्य हन्दा दानक

जानपुर स प्रकाशत

# देश की उपासना

## देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03

अंक - 35

जौनपुर, शनिवार, 21 सितम्बर 2024

## सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

## पेज - ८

मूल्य - 2 रुपये

## विश्वकर्मा योजना भारत के कौशल को जीवित रखने का रोडमैप - मोदी

2026 तक देश से होगा नवसलवाद का सफाया – शाह



वर्ष पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करना। अमरावती का शपीएम मित्र पार्कश इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा योजना की एक और विशेषता है। जिस स्केल पर, जिस बड़े पैमाने पर इस योजना के लिए अलग अलग विभाग एकजुट हुए हैं, ये भी अभूतपूर्व हैं। उन्होंने कहा कि देश के 700 से ज्यादा जिलों, 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत, 5 हजार शहरी स्थानीय निकाय मिलकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। मोदी ने कहा कि एक साल में ही 18 अलग-अलग पेशों के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ा गया। सिर्फ साल भर में ही 8 लाख से ज्यादा शिल्पकारों और

कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण मिल चुकी है। अकेले महाराष्ट्र में ही 60 हजार से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण मिली है। उन्होंने कहा कि अब तक 6.5 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा बंड युअॅ को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बढ़ी है। इतना ही नहीं, हर लाभार्थी को 15 हजार रुपये का ई-वाउचर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बिना गारंटी के 3 लाख रुपये तक लोन भी मिल रहा है। मुझे खुशी है कि एक साल के भीतर विश्वकर्मा भाई-बहनों को 1,400 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है।



ही उनके खिलाफ चौतरफा अभियान चलाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम नक्सलवाद को खट्टम करेंगे। मैं (नक्सलियों) से अपील करता हूं कि वे कानून के सामने आत्मसमर्पण कर दें, अपने हथियार छोड़ दें। उत्तर-पूर्व और कश्मीर में कई जगहों पर कई लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आपका भी स्वागत है लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसके खिलाफ अभियान चलाएंगे और इसमें सफलता भी मिलेगी। सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ अपने अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

संक्षिप्त खबरें

उत्तर प्रदेश का  
अगला विधानसभा  
चुनाव लड़ेगी लोक  
लोकार्पण समर्पण

हरियाणा में  
केरीवाल  
ने शुरू किया  
चुनावी प्रचार

<p>हरियाणा, एजेंसी। आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसी बीच आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के साथ हरियाणा में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। यह 11 जिलों में 13 निर्धारित रैलियों में से पहली थी। आपको बता दें कि केजरीवाल की पार्टी आगामी राज्य चुनाव में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आज केजरी वाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में कोई</p>	<p>1200 रुपए देते थे। उसको बढ़कर अब 3000 कर दिया है। यानि ढाई सौ परसेंट की वृद्धि। अगर किसी</p>	<p>दाम को यूपी सरकार ने 118 परसेंट बढ़ा दिया है। इसे 7967 से 17365 रुपए कर दिया है। यानि 118 परसेंट</p>	<p>में लंबे-लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली दी है। यही कारण है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जरुरी</p>	<p>मिलते हैं। आतिशी ने कहा कि यदि बीजेपी शासित अन्य राज्यों से तुलना की जाए।</p>
<h1>100 दिन की उपलब्धियों का लेरवा-जोरवा नड्डा ने पेश किया</h1> <p>नई दिल्ली, एजेंसी। जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश किया कि विस्तारित एबी-पीएमजेरवाई में 70 साल और उससे अधिक आयु के सभी लोग शामिल होंगा और करीब साढ़े चार करोड़ परिवारों में लगभग छह करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। नड्डा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। कई बार सत्ता में</p> <h2>समाचारों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता आज संकट में है - लोकसभा अध्यक्ष विरला</h2> <p>नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा अध्यक्ष ओम विरला ने दावा किया है कि संसद टीवी सदन की कार्यवाही को निष्पक्षता से प्रसारित करता है। संसद टीवी जनप्रतिनिधियों की आवाज के साथ-साथ संसद और आमजन के बीच प्रभावी कनेक्ट का</p> <p>तक पहुंचाकर इस कमी को पूरा करने में सराहनीय कार्य कर रहा है और सूचना के प्रामाणिक स्रोत के प्रौद्योगिकियों और एआई के उपयोग से संसद टीवी लोगों की आशाओं और सूचना के प्रामाणिक स्रोत के तीन वर्षीय अस्तित्व में संसद टीवी लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्कृति के उच्च मूल्यों को प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है।</p> <p>लोक तांत्रिक मूल्यों के प्रति विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। इधर, तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार को विभिन्न मुद्दों को लेकर घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दो दिन पहले नवादा में दलित समाज के लोगों के घर जलाए जाने को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।</p>				

# 100 दिन की उपलब्धियों का लेखा-जोखा नाई ने पेश किया

# समाचारों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता आज संकट में है - लोकसभा अध्यक्ष विरला

नई दिल्ली, एजेसी। जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों का लेखा—जोखा पेश कहा कि विस्तारित एबी—पीएमजे-एवाई में 70 साल और उससे अधिक आयु के सभी लोग शामिल

होगा और करीब साढ़े चार करोड़ परिवारों में लगभग छह करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। नड्डा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। कई बार सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दलों ने समाज को विभाजित किया और बोट बैंक की राजनीति जारी रखी। लेकिन अब, मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, समय बिल्कुल बदल गया है! उन्होंने कहा कि जब से प्रधान मंत्री मोदी जी सत्ता में आए हैं, हमारा देश प्रदर्शन की राजनीति, जवाब देही की राजनीति, वितरण की राजनीति और अंतिम—मील वितरण

नई दिल्ली, एजेंसी से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दावा किया है कि संसद टीवी सदन की कार्यवाही को निष्पक्षता से प्रसारित करता है। संसद टीवी जनप्रतिनिधियों की आवाज के साथ-साथ संसद और आमजन के बीच प्रभावी कनेक्ट का माध्यम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद टेलीविजन के स्थापना दिवस पर संसद भवन परिसर में आयोजित संसद टीवी कॉन्वलेच के समापन सत्र को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि आज समाचारों की विश्वस नीयता और प्रामाणिकता संकट में है। उन्होंने कहा कि संसदीय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में संसद



रूप में संसद टीवी की छाप देश और विदेश में विभिन्न हितधारकों को लाभान्वित कर रही है। उन्होंने

प्रौद्योगिकियों और एआई के उपयोग से संसद टीवी लोगों की आशाओं और आकंक्षाओं को और अधिक प्रभावी तीन वर्षीय अस्तित्व में संसद टीवी लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्कृति के उच्च मूल्यों को प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम बनकर

तीन वर्षीय अस्तित्व में संसद टीवी  
लोकतान्त्रिक परंपराओं और संस्कृ  
ति के उच्च मूल्यों को प्रदर्शित  
करने का एक सशक्त माध्यम बनकर

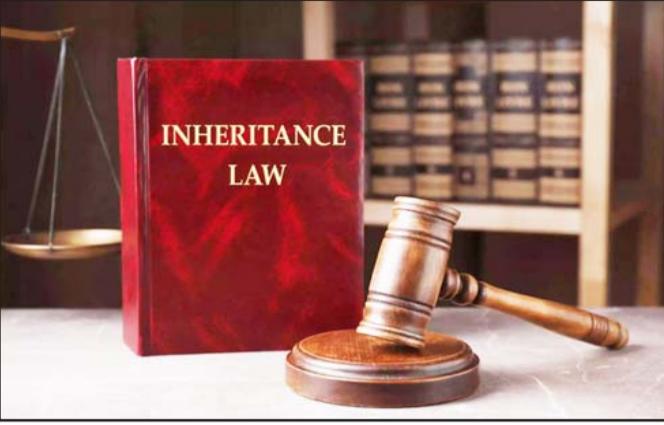
उभरा है।  
लोक तांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संसद टीवी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दे रहा है। संसद टीवी के माध्यम से लोग संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज, नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन से अवगत हो रहे हैं। साथ ही संसद टीवी के माध्यम से भारतीय संस्कृति, इतिहास और वर्तमान से जुड़े सरोकार

# संपादकीय

## दुरुपयोग की जवाबदेही

आंध्र प्रदेश में अभिनेत्री—मॉडल कादंबरी जेठवानी की गलत गिरफ्तारी के मामले में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के निलंबन ने सत्ता के दुरुपयोग और जवाबदेही की आवश्यकता के बारे में बहस छेड़ दी है। राज्य पुलिस में उच्च पदों पर आसीन पी. सीताराम अंजनेयुलु, क्रांति राणा टाटा और विशाल गुन्नी को आंतरिक जांच के बाद निलंबित कर दिया गया, जिसमें प्रक्रियात्मक विफलताओं का खुलासा हुआ। विवाद के केंद्र में यह तथ्य है कि श्री अंजनेयुलु ने कथित तौर पर एफआईआर दर्ज होने से पहले ही सुश्री जेठवानी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया था। एफआईआर 2 फरवरी को दर्ज की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी के आदेश कथित तौर पर दो दिन पहले दिए गए थे — जो उचित प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन है। कानूनी प्रक्रिया के प्रति यह उपेक्षा इस बात पर संदेह पैदा करती है कि कुछ अधिकारी किस तरह से अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। अगस्त में दायर सुश्री जेठवानी की शिकायत में अधिकारियों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता और फिल्म निर्माता केवीआर विद्यासागर के साथ संजिश रचने का आरोप लगाया गया था, जिन्होंने पहले उनके खिलाफ जालसाजी और जबरन वसूली के आरोप दर्ज किए थे। उनका दावा है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित थे, जिससे पहले से ही उलझी रिथ्ति और जटिल हो समाज के कानूना ढाँच का एक बुनियादी पहलू है, जो परिवारों के भीतर परिसंपत्तियों और धन का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करता है। भारत में, कई अन्य देशों की तरह, ये कानून सास्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में गहराई से समाए हुए हैं। हालांकि, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों से संबंधित संवैधानिक सिद्धांतों के साथ प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। महिलाओं के उत्तराधिकार से संबंधित इस्लामी कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएम पीएलबी) द्वारा हाल ही में स्वीकारोक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मान्यता भारत में अधिक मानकीकृत और

न्यायसंगत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए उत्तराधिकार कानूनों को संहिताबद्ध करने के बारे में स्वीकृति को दर्शाता है। भारत की न्याय व्यवस्था में धर्म के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों का एक जटिल पैदा होती है जहां महिलाओं को, उनके धार्मिक जु़ड़ाव के आधार पर, उत्तराधिकार के मामलों में असमान जाएंगे। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार सहित सुधारों के लिए समर्थन जुटाने तथा आम सहमति बनाने के टिप्पणी महत्वपूर्ण है। महिलाओं की विराज



महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। महिलाओं के उत्तराधिकार से संबंधित इस्लामी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में अंतराल की एआईएमपीएलबी की मान्यता एक स्वागत योग्य कदम है। यह उत्तराधिकार अधिकारों के संदर्भ में लैंगिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता की बढ़ती जाल है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर महिलाओं के लिए अलग-अलग उत्तराधिकार कानून बनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों के अपने-अपने उत्तराधिकार कानून हैं, जिसके कारण अलग-अलग प्रथाएं और व्याख्याएं होती हैं। इससे ऐसी स्थिति

पैदा होती है जहां महिलाओं को, उनके धार्मिक जुड़ाव के आधार पर, उत्तराधिकार के मामलों में असमान व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके आर्थिक सशक्तीकरण और समग्र प्रगति में बाधा आ सकती है। धार्मिक समुदायों में उत्तराधिकार कानूनों को संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया उत्तराधिकार के सिद्धांतों को मानकीकृत करेगी। जिससे सभी व्यक्तियों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना समान व्यवहार सुनिश्चित होगा। संहिताकरण समानता, न्याय और गैर-भेदभाव के संवैधानिक लोकाचार का पालन करते हुए विविध कानूनों को एक व्यापक कानूनी ढांचे में सुसंगत और सुव्यवस्थित कर सकता है। ऐसा कदम न केवल महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों को मजबूत करेगा बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं को भी सरल करेगा, जिससे वे आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगे।

भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। उत्तराधिकार कानूनों का संहिताकरण इन संवैधानिक प्रावधानों के साथ संरेखित होगा, एक समान दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा और लिंग, धर्म या जाति के आधार पर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करेगा। यह इस सिद्धांत को मजबूत करेगा कि कानून के सामने हर नागरिक समान है और समान सुरक्षा और लाभ का हकदार है। प्रयास उत्तराधिकार कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को इस पहल के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सके। धार्मिक नेतृत्वों, कानूनी विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों और नागरिकों सहित विभिन्न हित धारकों को शामिल करना, आवश्यक कानूनी सुधारों के लिए समर्थन जुटाने उम्मीद है। महिलाओं की विरासत से संबंधित इस्लामी कानूनों प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता बारे में अप्डेट की मान्यता समान नागरिक संहिता के तहत प्रस्तावित समान कानूनों के अनुशंसा प्रतीत होती है। अप्डेट के प्रयासों को भारत में विरासत कानूनों का धार्मिक सीमाओं से परे संहिताबद्ध करके एक व्यावहारिक कदम बदलना चाहिए, जो कि यूसीसी तहत आसानी से संभव है। इस एकरूपता, समानता और न्याय सुनिश्चित होगा, विरासत कानूनों को संवैधानिक ढांचे के साथ संरेखित किया जाएगा और सभी के लिए समानता के सिद्धांत को कायम रखा जाएगा। इस परिवर्तन को आगे बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक भागीदारी उम्मीद है, जो अंत में एक अधिक समावेशी और प्रगतिशील समाज को बढ़ावा देगा।

# **महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों को आगे बढ़ाना**

आदित्य उत्तराधिकार कानून समाज के न्यायसंगत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए उत्तराधिकार कानूनों को संहिताबद्ध करने के बारे में न्यायसंगत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए उत्तराधिकार कानूनों को संहिताबद्ध करने के बारे में स्वीकृति को दर्शाता है। भारत की न्याय व्यवस्था में धर्म के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों का एक जटिल पैदा होती है जहां महिलाओं को, उनके धार्मिक जु़ड़वाके आधार पर, उत्तराधिकार के मामलों में असमान व्यवहार का समाना करना पड़ जाएंगे। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार सहित सुधारों के लिए समर्थन जुटाने और आम सहमति बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं की विरासत में संरक्षित दस्तावधारी कानूनों

The image shows a book titled "INHERITANCE LAW" with a red cover, a wooden gavel, and a balance scale on a desk, symbolizing the legal and ethical aspects of inheritance.

# विश्व में नंबर 1 बनने के लिए बड़ा लक्ष्य

विनोद

भारत ने एशियाई चौपियस टीम (एसीटी) खिताब की रक्षा के लिए जीत के साथ शुरुआत की पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहकर कड़ी महनत को, जिसमें डिफेंडर जुगराज सिंह द्वारा 51वें मिनट में एक दुर्लभ फील्ड गोल शामिल था। लगातार दूसरी बार एशियाई चौपियस ट्रॉफी जीतना वास्तव में बहुत खुशी की बात है और इससे पहले 2016 और 2018 में लगातार खिताब हासिल किए थे। इस प्रकार, भारत रिकॉर्ड पांच खिताबों के साथ टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम बन गई। हालांकि, दृढ़ संकलिप्त चीनी टीम के खिलाफ एकमात्र गोल विजेता, जो केवल अपने दूसरे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में खेल रही थी, ने भारतीय पक्ष की तैयारियों पर एक छाया डाली जो चार दशक की पर है। इससे पहले, चीन ने किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में केवल 2006 के एशियाई खेलों में भाग लिया था, जहां वे कोरिया से 1-3 से हारने के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। एशियाई चौपियस ट्रॉफी के अलावा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत आठ स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ ओलंपिक इतिहास में सबसे सफल हॉकी टीम थी। भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। दूसरी ओर, पाकिस्तान पुरुष हॉकी विश्व कप में सबसे सफल देश है, जिसने चार खिताब (1971, 1978, 1982 और 1994) जीते हैं, जबकि नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने तीन-तीन विश्व कप जीते हैं। पदक हासिल किया। रिकॉर्ड आठ बार ओलंपिक चौपियन और पांच बार एशियाई चौपियस ट्रॉफी विजेता होने के बावजूद, भारतीय हॉकी टीम केवल एक विश्व कप खिताब जीतने में सफल रही है। भारत की एकमात्र जीत 1975 में अजीत पाल सिंह की कप्तानी में कुआलालंपुर में पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी। भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। दूसरी ओर, पाकिस्तान पुरुष हॉकी विश्व कप में सबसे सफल देश है, जिसने चार खिताब (1971, 1978, 1982 और 1994) जीते हैं, जबकि नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने तीन-तीन विश्व कप जीते हैं। प्रायोजकों की कमी और क्रिकेट को प्रमुखता इस खेल में गिरावट के कारणों में से एक है। खेल में विकास के एक हिस्से के रूप में फील्ड हॉकी से ऑफसाइड नियम अतीत पर गर्व हो सकता है, जिस लगभग एक सदी तक इस खेल बोर्ड सफलता हासिल की है, लेकिन 1980 के बाद से टीम की अचानक गिरावट को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर भारत हॉकी रैकिंग शुरू होने के बाद से कभी भी दुनिया की नंबर एक टीम नहीं रही है। तब भारत छठे स्थान पर था। 2008 में भारत 80 वर्षों में पहली बार बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने में विफल रहा और उनके निराशाजनक प्रदर्शन के कारण गई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम वर्तमान में पांचवें स्थान पर जब भारतीय हॉकी को अपने गोरवशाली अवधि पर गर्व हो सकता है, जिस लगभग एक सदी तक इस खेल बोर्ड सफलता हासिल की है, लेकिन 1980 के बाद से टीम की अचानक गिरावट को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर भारत हॉकी वैश्विक महाशक्ति के रूप में फिर उभरना चाहता है, तो उसे बेहतर प्रदर्शन करने और वर्षों तक बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालीफाई होगा और 2026 में विश्व कप 3 ओलंपिक के लिए पसंदीदा के रूप में आगे बढ़ना होगा।

पदक और कुल मिलाकर 13वां पदक हासिल किया। रिकॉर्ड आठ बार ओलंपिक चौपियन और पांच बार एशियाई चौपियस ट्रॉफी विजेता होने के बावजूद, भारतीय हॉकी टीम केवल एक विश्व कप खिताब जीतने में सफल रही है। भारत की एकमात्र जीत 1975 में अजीत पाल सिंह की कप्थानी में कुआलालंपुर में पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी। भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। दूसरी ओर, पाकिस्तान पुरुष हॉकी विश्व कप में सबसे सफल देश है, जिसने चार खिताब (1971, 1978, 1982 और 1994) जीते हैं, जबकि नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने तीन-तीन विश्व कप जीते हैं।

भारत में एस्ट्रोटर्फ की कमी, प्रायोजकों की कमी और क्रिकेट को प्रमुखता इस खेल में गिरावट के कारणों में से एक है। खेल में विकास के एक हिस्से के रूप में फील्ड हॉकी से ऑफसाइड नियम को समाप्त करने से भारतीय हॉकी की मुश्किलें और बढ़ गईं। भारी प्रभुत्व के बावजूद, भारतीय पुरुष टीम 2003 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की आधिकारिक हॉकी रैंकिंग शुरू होने के बाद से कभी भी दुनिया की नंबर एक टीम नहीं रही है। तब भारत छठे स्थान पर था। 2008 में भारत 80 वर्षों में पहली बार बींजिंग ओलंपिक के लिए व्यावालीफाई करने में विफल रहा और उनके निराशाजनक प्रदर्शन के कारण रैंकिंग गिरकर 12वें स्थान पर गई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम महिला टीम नौवें स्थान पर भारतीय हॉकी को अपने गौरवशाली अंतीम पर गर्व हो सकता है, जिसका लगभग एक सदी तक इस खेल बैजोड़ सफलता हासिल की है, लेकिन 1980 के बाद से टीम की अचानक गिरावट को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर भारत हॉकी वैश्विक महाशक्ति के रूप में फिर उभरना चाहता है, तो उसे बेहतुरी प्रदर्शन करने और वर्षों तक बींजिंग हासिल करने का लक्ष्य रखना होगा और 2026 में विश्व कप 3 ओलंपिक के लिए पसंदीदा के रूप में आगे बढ़ना होगा।

# देश के सम्पूर्ण विकास के लिए पर्यटन के साथ-साथ प्रकृति पथ का उत्थान करें

प्रोफे. जी० सी० पाण्डे ये,  
वर्ती सम्मान प्राप्त, पर्यावरणविद  
भारत विश्व में पर्यटन के लिए  
दब्द है। देश एवं विदेश के लाखों  
गनी मनोरम, मनोरंजक स्थल,  
च्छादित गगनचुम्बी पर्वत  
लाए, तीर्थ स्थल, फूल भरे  
न, नीची और ऊँची घाटियां,  
छवि खारे पानी की झीलें, अन्य  
पक्षी जैव विविधता से भरे बन,  
किनारे के खूबसूरत नजारे,  
एवं सलोन मार्ग एवं जल प्रपात  
ने को आते हैं। इकोटूरिज्म  
ना के अन्तर्गत देश में नये—नये  
टन स्थल विकसित किये जा  
हैं। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के  
पर विकास किया जा रहा है,  
पर्यटक घूमने फिरने और  
तीर्थ स्थलों की यात्रा करने  
साथ—साथ प्रकृति के विराट  
न करके पर्यावरण के संरक्षण  
परी आत्म सेवात्म ते राहे।

टूरिज्म शब्द 1983 में हेक्टर सिबेतास ला स्कुरियन ने दिया था। जिसका अर्थ लिया गया प्रकृति आधारित पर्यटन। जिसमें शामिल है प्रकृति के प्रति शिक्षा प्रबन्धन और विकास। पर्यटन एक ऐसा शब्द है कि प्रत्येक व्यक्ति सुनकर खुश होता है और इच्छा रखता है कि घर से दूर कहीं भी सुकून की जिन्दगी बितायें, जिसमें बच्चे ज्यादा खुश होते हैं। इसमें स्थानीय लोगों की सुदृढ़ भागीदारी निश्चित हो और प्रकृति और पर्यटन आधारित व्यवसायों से जुड़कर पर्यावरण सुरक्षा और विकास स्थानीय निवासियों की मदद से किया जा सके।

प्रकृति आधारित पर्यटन के मुख्य सरोकार इस तरह निर्धारित किये गये हैं—

1. प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रति क्षमाता पार्श्वकर्तरों में

५ पैदा  
वेकास,  
कंकरीट  
मिट्टी  
  
जन्मुओं  
पर्यटन  
योजना  
  
पहाड़ों  
विहार,  
भूमियों  
प्राणी  
दर्शन  
लिए  
  
स्पतियों  
के नये  
और  
न-जन

६. स्थ  
संस्कृति, भाषा  
स्थलों में प्र  
कलाकारों, फ  
कवियों, नाट्य  
पर्यावरण इति  
  
७. पर्याव  
वाले वाहनों  
बायो डीजर  
बाजार में र  
बनाना।  
  
८. इको  
ऐसे प्रतिभास  
प्रकृति से ज  
लोक आस्त  
इतिहास लो  
गीत, संगीत  
लेते हों, उ  
लिए प्रशिक्ष  
गाइडस फ  
पर्यावरण र  
पाए।

नीय लोक कला, व वेश भूषा को पर्यटक दर्शित करके स्थानीय त्रकारों, हस्त शिल्पियों, काकारों के माध्यम से क्षा अभियान चलाना। परण को प्रदूषित करने वो हटाकर, सौर ऊर्जा, आधारित वाहनों को तारना और लोकप्रिय रिञ्जम गाइड के लिए ली युवक-युवतियों जो डी वैदिक परम्पराओं, आओं, लोक कलाओं, लोककलियों, मुहावरों, लोक में निपुण अथवा रुचि हें पर्यटक स्थलों के देकर इकोटूरिज्म युक्त करना ताकि खिलवाड़ रोका जा

9. पर्यटक स्थलों पर पर्यावरण से जुड़े बहुयाहरित दिवसों पर विशेष इकोटूरिज्म समारोहों, संगोष्ठियों, कवि सम्मेलनों और लोकगीतों का आयोजन करवाना।

10. स्थानीय भाषाओं में जैव विविधता के उपयोग व संरक्षण के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक स्थलों पर पेड़-पत्ती पहचान प्रतियोगिता, पेड़ परिचर्चा, वन्य फूल प्रदर्शनी, आयुर्वेद दवाईयों के घटक पौधों का वितरण आदि शामिल करना।

11. विभिन्न उत्सवों में मेला का आयोजन स्थानीय लोगों की भागीदारी से करने पर सहमति जुटाना।

12. पुलिस-पब्लिक मेले की तर्ज पर जंगल-जन मेला 21 मार्च वानिकी दिवस पर आयोजित करने की योजना लागू करने का प्रयास करना।

13. प्राचरणों, प्रचं, प्राचरों में

जगह—जगह पर्यावरण को बचा के लिए स्लोगन स्थापित किया जाये ताकि लोग—बाग जागरूक हों, जैसे जल ही जीवन है, वृक्ष जीवन है, पृथ्वी मां है, हमारा भवित्व वृक्ष पर निर्भर है।

14. इकांटूरिजम को अलोकप्रिय बनाने की दिशा में देश के सभी प्रदेशों में मनोरम प्रकृति पथ घोषित होने चाहिये जहां सैलानी आकर प्राकृतिक सौन्दर्य का आनंद ले सकें। शासन द्वारा सड़कों किनारे, नदियों के किनारे, शहर किनारे, देवालयों के पास या अन्य विशेष स्थानों पर महापुरुषों, शहीदों के नाम से या राष्ट्रीय फल, फूल, वृक्ष, जानवर, पवित्र नदियों के नाम से प्रकृति पथ बनायें ताकि उनका नाम अमर हो सके और देशभाषी की भावना भी विकसित की जा सके। पर्यावरण बचेगा तो वे सदृश सांस्कृति-सांस्कृतिक देश-

## चुनाव में कांग्रेस के 'फ्री ऑफर' से सत्ता की चाबी

अजय भारतीय राजनीति में मुफ्त योजनाओं का चलन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, और यह एक ऐसी रणनीति बन गई है जिसे कांग्रेस ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कई आर्कषक वादे पेश किए हैं। इनमें से प्रमुख वादा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का है, जो सीधे अर्थिंद केजरीवाल का मुफ्त पानी और बिजली देने का मॉडल हो या अभियानों में बड़ी चतुराई से इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुफ्त पानी और बिजली देने का कार्यक्रम, ये सभी नीतियां राजनीतिक सफलता की कुंजी बन चुकी हैं। परिचम बंगाल की ममता बनर्जी से लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तक, सभी अपनी सत्ता को मजबूत किया है।

जिससे वह पिछले दस वर्षों से सत्ता से बाहर रहने की स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है।

कांग्रेस ने उस राजनीतिक दल अपने चुनावी विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कई आर्कषक वादे पेश किए हैं। इनमें से प्रमुख वादा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का है, जो सीधे अर्थिंद केजरीवाल के मॉडल से प्रेरित है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस ने समझ लिया है कि विधायाओं को भी छह हजार रुपये की पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। किसानों को आर्कषित करने के लिए कांग्रेस ने एमएसपी (चूनूतम समर्थन मूल्य) को कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। यह घोषणा किसानों के हित में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने गांधी-समर्थन की चिन्हाएँ

की प्रत्येक महिला को प्रतिमाह 2000 रुपये देने का वादा किया है। यह योजना मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से प्रेरित है, जिसने उस राज्य में चुनावी परिणामों को पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस का यह वादा महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपने पक्ष में करने की एक रणनीति है। इसके अतिरिक्त, बुजुर्ग, दिव्यांगों और विधायाओं को भी छह हजार रुपये की पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक जीत की कुंजी हो सकती है। कांग्रेस के नेता इस बार अपने वादों में आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं, और उन्होंने इन योजनाओं को लुभावना बनाने की हर संभव कोशिश की है। महिलाओं के प्रति कांग्रेस का यह नया दृष्टिकोण भी ध्यान देने चाहिए।

कांग्रेस ने गांधी-समर्थन की चिन्हाएँ

को समझा है। भारतीय राजनीति में किसानों का एक अहम स्थान है, और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद रहा है। इसके अलावा, कांग्रेस ने किसानों को तुरंत मुआवजे का आश्वासन देकर उनकी समस्याओं को तेजी से हल करने का भी वादा किया है। हालांकि कांग्रेस ने तेलंगाना के मॉडल को भी अपनाने की कोशिश की है, जिसमें गैरेस सिलेंडर के लिए मात्र 500 रुपये देने का प्रस्ताव है। यह योजना गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके तहत 100 गज के मुफ्त प्लॉट और पक्के मकान देने का भी भरोसा दिया है, जो सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी मांग है। इस योजना से न केवल कर्मचारियों को, बल्कि उनके परिवारों को भी फायदा होगा, और इससे कांग्रेस का समर्थन बहु संकृत है। चुनावी चालान

में कांग्रेस ने अपनी योजनाओं को प्रभावशाली तरीके से पेश किया है, जो दर्शाता है कि वह अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए हर संभव

को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसके तहत गरीबों के लिए 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता पर हाल के वर्षों में सवाल उठते रहे हैं, और यह योजना कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण दांव साबित हो सकती है। हालांकि राजस्थान में यह योजना अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर पाई थी, लेकिन हरियाणा में इसकी लोकप्रियता को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का भी भरोसा दिया है, जो सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी मांग है। इस योजना से न केवल कर्मचारियों को, बल्कि उनके परिवारों को भी फायदा होगा, और इससे कांग्रेस का समर्थन बहु संकृत है। चुनावी चालान

में कांग्रेस ने अपनी योजनाएं हमेशा कारगर नहीं होतीं। कई बार मतदाता इन योजनाओं के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण रणनीति अपनी है। अब देखना यह है कि क्या मुफ्त योजनाएं वास्तव में उन्हें सभी में वापस लाने में मदद कर पाएंगी। भाजपा और अन्य दलों की प्रतिक्रियाएं भी इस चुनाव यह सारी हरियाणा का चुनाव है। अंत में, कांग्रेस ने अपनी योजनाएं कितनी प्रभावशाली हैं और क्या वे एक राजनीतिक दल की किस्मत को बदलने सक्षम हैं। कांग्रेस की यह कोशिश एक संकेत है कि चुनावी राजनीतिक समर्थन की योजनाएं अब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अंत में, कांग्रेस के लिए राजनीतिक सफलता की चाली बाज़ पाएंगी।

में कांग्रेस ने अपनी योजनाओं को प्रभावशाली तरीके से पेश किया है, जो दर्शाता है कि वह अपने मतदाताओं को उपर करने के लिए हार्दिक संभावना कि मुफ्त योजनाएं हमेशा कारगर नहीं होती। कई बार मतदाता इन योजनाओं के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण मद्दें को भी ध्यान में रखते हैं।



प्रयास कर रही है। हालांकि, कांग्रेस के इन दावों की सफलता केवल चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगी। गणनीयिक विपक्षों का कहना है कि भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और कानून-व्यवस्था की स्थिति जैसे मुद्दे भी मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करते हैं। इस प्रकाश हिंस्याएँ रखा है।



